Seventeenth Loksabha

an>

Title: Issue regarding shortage of drinking water in Dausa Parliamentary Constituency, Rajasthan.

श्रीमती जसकौर मीना (दौसा): सभापति महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र दौसा में पेयजल संकट की इतनी गंभीर समस्या है कि पिछले आठ दिनों से आठ घंटे में एक घंटा भी पानी नहीं आ रहा है । भूमिगत जल के सारे स्रोत सूख चुके हैं । जल-जीवन मिशन के अंतर्गत मेरे यहां 49 ग्राम पंचायतों के लिए स्वीकृति दी गई । लेकिन राज्य सरकार की अकर्मण्यता के कारण वे प्रारंभ नहीं हुए और कहीं-कहीं वहां के विधायकों के द्वारा केवल पत्थर गाड़ दिया गया, लेकिन स्कीम चालू हो कर पेयजल उपलब्ध नहीं कराया गया ।

मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि जल-जीवन मिशन द्वारा स्वीकृत योजना जितनी भी हैं, उनका शुभारंभ और उनकी पूर्णता में जब तक क्षेत्रीय सांसद को इनवॉल्व नहीं किया जाएगा, तब तक मैं सोचती हूँ कि इसका सही क्रियान्वयन और सही लाभ जनता को नहीं मिल पाएगा । मैं ऐसी स्थिति में आपके माध्यम से केंद्र सरकार से भी अनुरोध करना चाहूंगी कि जहां-जहां भारत सरकार की नीतियों का धन जाता है, चाहे वह जल-जीवन मिशन के अंतर्गत हो, चाहे अटल भूजल योजना के अंतर्गत हो, इन सभी योजनाओं को संचालित करने के साथ-साथ मॉनिट्रिंग किया गया । दिशा की कमिटी में हम कितनी भी बात कर लें, लेकिन उसके बावजूद भी वहां विरोधी सरकारों के कान पर जूं भी नहीं रेंगती है । ऐसी स्थिति में इस समस्या का समाधान तभी हो सकेगा, जब हम कम से कम भारत सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करने के साथ-साथ उसमें क्षेत्रीय सांसदों को जोड़ेंगे ।

दूसरी बात मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि पेयजल संकट आज का नहीं है । वर्षों से दौसा संसदीय क्षेत्र पूरा डार्क जोन है । उसमें मेरा बांदीकुई विधान सभा क्षेत्र तो ऐसा है जिसमें पीने का पानी दो-दो, तीन-तीन किलोमीटर दूर से माथे पर लाया जाता है या टैंकरों से भरा जाता है । उसका निदान एक ही है कि ईसरदा

बांध के माध्यम से दौसा जिले की पांचों विधान सभाओं को जो पेयजल उपलब्ध होना था, उसमें शीघ्रता की जाए, क्योंकि उसमें केंद्र सरकार का भाग जा चुका है । इसके लिए राज्य सरकार को प्रतिबद्ध किया जाए कि वे इस योजना को जल्दी से जल्दी प्रारंभ कर के पेयजल की समस्या का निराकरण करे ।